CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED SCARCITY OF DIESEL IN U.P. AND OTHER PARTS OF THE COUNTRY

श्री काजी जलील अब्बासी (डुमरियागंज): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"उत्तर प्रदेश और देश के अन्य भागों में डीजल की कमी, जिसके परिणामस्वरूप किसानों के लिए गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है, का समाचार"

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): Sir. Honourable Shri Jalil Abbasi and four other Members have drawn attention regarding the reported scarcity of diesel in U.P. and other parts of the country resulting in a serious crisis for the farmers. The position is indicated below:

The system of monthly allocations of High Speed Diesel (HSD) to different States and Union Territories was first introduced from October, 1979. This worked satisfactorily and during the monsoon months in this year the State Governments withdrew the regulatory measures due to adequate availability of the product and a slum in demand.

During the last week of Septmeber this year, there was a sudden spurt in demand largely due to panic buying following the outbreak of Iran-Iraq war. In order to effectively control the situation the State Governments were asked in October to regulate the distribution of diesel once again giving the highest priority to agriculture.

The allocations of diesel for the months of October to December 1980 have been made at a level 5 per cent higher than original allocations of the product in the corresponding months of the previous year. Ad-hoc extra allocations were also made from time to time to different States as per their requirements. Thus, the allocations of HSD for October and November, 1980, were increased from 684,000 tonnes and 736,000 tonnes by 14,000 tonnes and 40,000 tonnes respectively. The original allocation for the month of December, 1980, was 757,000 tonnes which has been further increased by 52,000 tonnes to the needy States.

In order to ensure availability of the product, required imports have been made and with constant liaison with the Railways sufficient movement of the product has been maintained for all the States. Road movement, where necessary, has also been augmented.

As regards Uttar Pradesh, the original allocation of 78.800 tonnes of HSD for October, 1980 was raised by 3,200 tonnes. The November and December allocations have been maintained at very high levels of 94,000 tonnes and 92,000 tonnes respectively.

The situation of all the States is monitored on day-to-day basis and where necessary further product is provided.

I would like to assure the Hon'ble Members that there is no shortage of the product in the country. We have sufficient stocks and, if required, further imports would be made. I may once again stress that the distribution of HSD within the States is done by the State Governments who have been repeatedly impressed upon to give the first priority in the allocation of HSD for agriculture and to ensure that agricultural requirements do not suffer on account of any other constraints. The State Governments have also assured us in the meetings recently taken with the Secretaries of the State Governments that there is no problem of supplies for agriculture, as requisite allocations have been made for that sector.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Kazi Jalil Abbasi....

(*Interruptions*)

SHRI DHANIK LAL MANDAL: As a protest against your behaviour, I walk out, Sir.

Shri Dhanik Lal Mandal and some other hon. Members then left the House.

MR. DEPUTY SPEAKER: Mr. Kazi Jalil Abbasi. You please put your questions....

(*Interruptions*)

DR. SUBRAMANIAM SWAMY (Bombay North-East): On a point of order, Sir. Rule 360 says:

"The Speaker may himself, or on a point being raised or on a request made by a member, address the House at any time on a matter under consideration in the House with a view to aid members in their deliberations, and such expression of views shall not be taken to be in the nature of a decision."

SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur): Sir, how do you allow a point of order during Call Attention? It is a convention in the House that during call attention no points of order are allowed. When we raise from this side, you do not allow. How do you allow him to raise, Sir?

MR. Deputy-Speaker: Does it relate to the call attention, Dr. Subramanium Swamy?

DR. SUBRAMIAM SWAMY: It relates to the business before the House.

MR. DEPUTY-SPEAKER: No, no. This is Call Attention. It has nothing to do with it.

Mr. Kazi Jalil Abbasi.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Sir, as a protest I walk out, Sir.

Dr. Subramaniam Swamy then left the House.

SHRI K. MAYATHEVAR: (Dindigul): Mr. Deputy Speaker, Sir, yesterday I was also present on the atroctiy of....**

SHRI K. MAYATHEVAR: (Dandinot go on record.

Mr. Kazi Jalil Abbasi.

SHRI NIREN GHOSH (Dum Dum): I have walked out and come back.

SHRI K. MAYATHEVAR: **

MR. DEPUTY-SPEAKER: It will not go on record.

श्री काज़ी जलील अब्बासी : उपाध्यक्ष जी, यह जो मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है, उस के जवाब में मंत्री जी ने यह कहा है :

"I may once again stress that the distribution of HSD within the States is done by the State Governments who have been repeatedly impressed upon to give first priority in the allocation of HSD for agriculture."

मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब आपने एक बार यह कह दिया था कि एग्रीकल्चर को प्रायरिटी दी जाएगी और हमारे पास डीजल की कोई कमी नहीं है, तो देहातों के अन्दर जो पेट्रोल पम्प हैं, उन को कोटा कम क्यों मिल रहा है । डीजल का जो कोटा आप दे रहे हैं, वह शहरों में जो पेट्रोल पम्प हैं, उन को ज्यादा दे दिया जाता है । जितना एलोटमेंट होता है, वह सब शहरों में चला जाता है और देहातों में कोटा बहुत कम पहुंचता है । जब कि देहातों को डीजल की बहुत ज्यादा जरूरत है और वहां पर प्रायरटी देने की बहुत जरूरत है । इस वक्त जो डीजल दिया जा रहा है, उस की कमी के कारण हमारे यहां देहातों में वैसी ही

**Not recorded.

लाइनें दिखाई देती हैं जैसी कि 1977 में जनता पार्टी के जमाने में दिखाई देती थीं। उसी तरह के जमाने से आज हम गुजर रहे हैं। इसलिए मेरा कहना यह जो कोटा आपने एलाट किया है, उसको मेहरबानी कर के आप बढ़ाइए। मैं आप को कुछ फीगर्स देना चाहता हूं। अप्रैल में हमारे प्रदेश का कोटा 90 हज़ार मीट्रिक टन था, मई में 1 लाख मीट्रिक टन, जून में 88,800 मीट्रिक टन, जुलाई में 88,800 मीट्रिक टन, अगस्त में 70,700 मीट्रिक टन, सितम्बर में 76,300 मीट्रिक टन हो गया, अक्तूबर में 82,000 मीट्रिक टन और फिर नवम्बर में 94,000 मीट्रिक टन और अब दिसम्बर में आप ने फिर 92,000 मीट्रिक टन कर दिया है जब कि हमारे यहां की डिमाण्ड 1 लाख 25 हज़ार मीट्रिक टन की है। मई में आप 1 लाख मीट्रिक टन दे चुके हैं लेकिन उसके बाद आपने इसमें कटौती कर दी। अब फिर आपने इसको बढ़ाया है लेकिन हमारे यहां की डीमाण्ड 1 लाख 25 हज़ार मीट्रिक टन से कम नहीं है। इतना बड़ा हमारा प्रदेश है और उसके लिए जो कोटा आप दे रहे हैं वह बहुत कम दे रहे हैं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो कोटा आप दे रहे हैं, वह सही जगह पर नहीं पहुंच रहा है। शहर के बड़े बड़े लोग सारा कोटा ले लेते हैं और देहात के लोगों तक वह नहीं पहुंच रहा है। वे दो इम्पोर्टेन्ट बातें हैं, जो मैंने आपके सामने रखी हैं। इसी सिलसिले में एक बात मैं यह और कहना चाहता हूं कि अक्तूबर में अख़बारों में आपका बयान छपा है कि एग्रीकल्चर को इस मामले में प्रायरटी दी जाएगी। मैं ज्यादा तफ़सील में इस वक्त नहीं जाना चाहता क्योंकि यह तफ़सील देने का मौका नहीं है लेकिन इतना ही कहना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर को आप प्रायरटी दीजिए।

एक चीज और कहना चाहता हूं कि बम्बई के 8 नवम्बर के अख़बारों में यह निकला था :

'Black-market in Diesel in Bombay.'

बम्बई का कोटा हमारे यहां से बहुत ज्यादा है और वहां पर ब्लैक मार्केटिंग भी होती है। उनको ज्यादा कोटा मिलता है जब कि यू० पी० को सबसे ज्यादा कोटा मिलना चाहिए। मैं और ज्यादा न कहते हुए आपकी तवज्जह इस बात की तरफ़ दिलाना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश का कोटा बढ़ाया जाय।

एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि डीजल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके लिए इण्डियन आयल वाले कभी 1978 को बेस मान लेते हैं और कभी 1979 को बेस मान लेते हैं। बड़े बड़े पेट्रोल पम्प वाले, जो शहरों में हैं, उनको ही ज्यादा सुविधाएं दे दी जाती हैं और आप इस चीज की तरफ़ देख नहीं पाते हैं। कुछ मख़सूस किस्म के लोग ज्यादा कोटा ले जाते हैं और हमारे यहां देहात के लोगों को कोटा बहुत कम मिलता है। इस तरफ़ आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं और जो थोड़ा सा कोटा आपने बढ़ाया है, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं लेकिन जितनी हमारे यहां डीजल की जरूरत है, उसके हिसाब से आप कोटा दीजिए।

एक और बात यह कहना चाहता हूं

[श्री काजी जलील अब्बासी]

कि देहातों में जहां पर पेट्रोल पम्प नहीं हैं, वहां पर नये पेट्रोल पम्प खोले जाएं। आप के यहां से काफ़ी अर्से से नये पेट्रोल पम्प का खोलना बन्द हो गया है। पेटी डीलर्स के द्वारा जो तेल दिया जाता है, वह कुछ जगहों पर ही मिलता है और उसमें हर ड्रम में दस, दस और बारह, बारह लीटर का नुकसान हो जाता है। इसलिए देहात के इलाकों में पेट्रोल पम्प खोले जाएं और शहरों के पेट्रोल पम्पों के मुकाबले में उनको ज्यादा कोटा दिया जाए और 1978 और 1979 के कोटे का ख्याल न कर के देहातों की जरूरतों के मुताबिक उन को कोटा दिया जाए। इसके साथ मैं यह भी चाहूंगा कि इसमें जो ब्लैक-मार्केटिंग होती है, उसको रोका जाए। मैं मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वे इस तरफ़ विशेष ध्यान दें क्योंकि देहातो में अब जब हम जाएंगे तो वहां पर हमको लम्बी-लम्बी लाइने लोगों की लगी हुई मिलेंगी। इस के अलावा हर हफ्ता हमारे पास तार और टेलीफोन से सूचना आ रही हैं कि वहां पर डीजल की बहुत परेशानी है। उन लोगों को परेशानी न भुगतनी पड़े, इसका आप इन्तज़ाम कीजिए।

मान्यवर, मैं आपका बहुत मशकूर हूं कि आपने मुझे अपनी बातें कहने का मौका दिया और मंत्री जी ने जो सहूलियतें दी हैं उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। मैंने जो प्रश्न पूछे हैं, उनके बारे में मंत्री जी बताएं।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने अपने मूल बयान में कहा है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की स्थिति देश में असम बंद की वजह से, इराक-ईरान की लड़ाई की वजह से काफी खराब हो जानी चाहिए थी, इस बात को मद्देनजर रखते हुए भी खराब नहीं हुई क्योंकि प्रधान मंत्री जी ने अपने असरात का उपयोग किया और उसकी वजह से हमारी स्थिति काफी सुधरी और क्रूड की और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की अब कोई कमी नहीं है।

असल में पेट्रोलियम प्रोडक्टस में पांच परसेंट ग्रोथ का हिसाब लगा कर देखें तो यह मुनासिब है और यही ग्रोथ रेट होना चाहिए। यह दूसरी बात है कि कभी सूखे की वजह से, कभी पावर जेनरेशन में कमी की वजह से डीजल की मांग बढ़ जाती है और वह भी कुछ इलाकों में बढ़ जाती है कुल मिलाकर देखें तो डीजल की इफ़रात है, कोई कमी नहीं है। हमने पांच परसेंट ग्रोथ रेट के हिसाब से पिछले साल के मुकाबले में इस साल कहीं ज्यादा दिया है 1979 के अक्टुबर के मुकाबले में हमने सारी स्टेट्स को इस साल अक्टुबर में 6 लाख 98 हजार टन दिया, पिछले साल नवम्बर के मुकाबले में 7 लाख 76 हजार टन दिया। इन दो महीनों में सारी स्टेट्स को इतनी हमारी अलोकेशन थी। इससे आप अन्दाजा लगाइये कि पांच परसेंट ग्रोथ रेट के हिसाब से भी हमने कहीं ज्यादा इस साल अलोकेशन की है।

जहां तक उत्तर प्रदेश का ताल्लुक है इस साल अक्टुबर में हमने 82 हजार टन दिया था, नवम्बर, में 12 हजार टन बढ़ा कर 94 हजार टन दिया। 18 दिसम्बर तक 53 हजार 739 टन जा चुका है। 55 हजार 517 टन जो डिपो के पास था वह भी उन्होंने बेचा है। इस तरह से जो एक्चुअल एलोकेशन था उस से भी ज्यादा वहां बिक चुका है। इस तरह से अगर आप हिसाब लगा कर देखें तो करीब करीब एक लाख टन के करीब यू०पी० का एलोकेशन आ जाता है जो उसी एलोकेशन के बराबर है जो चौधरी चरण सिंह ने जब कि वे प्रधान मंत्री थे तब उनके कहने से केवल उत्तर प्रदेश के लिए किया गया था। उस समय उनके कहने से केवल उत्तर प्रदेश को एक लाख टन का कोटा अलोट कर दिया गया

था। जबकि और सब राज्यों का 15 से 25 परसेंट तक काट दिया गया था।

इस चीज क. मद्दे नजर रखते हुए उत्तर प्रदेश को इस साल काफी कोटा अलोटा किया गया है। किसी जगह पर यह शिकायत हो सकती है कि पेट्रोल पम्पों पर माल नहीं बिकता हो। मनिटरिंग स्टेट गवर्नमेंट करती है। हम बराबर स्टेट गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित करते रहते है कि खास कर एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। अगर उसमें कोई कठिनाई हो तो उसके लिए हमसे किसी महीने के लिए कोई विशेष अलोकेशन मांगना चाहे तो वह भी हो सकता है। दो-तीन बार मुख्य मंत्री जी मुझ से मिल चुके है और जो अलोकेशन हुआ है उससे वे संतुष्ट है। माननीय सदस्य के किसी खास ग्रामीण इलाके में यदि कोई खास कठिनाई हो तो उसके बारे में वे मुझे लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कठिनाई का कोई हल निकाला जाए।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया वह पूर्णत: असंतोषजनक है। जो लोग कह रहे है, उसके विपरीत काम हो रहा है देश के अन्दर डीजल का भंयकर दुर्भिक्ष पड़ा हुआ है। डीजल के बगैर किसान जिस तरह से परेशानी उठा रहे है उसकी जानकारी मंत्री जी को भी होगी क्योंकि वह मध्यप्रदेश से आते है।

हमारे उत्तर प्रदेश में किसान हर डीजल के पम्प पर दो-दो दिन तक लाइन लगा कर खड़े रहते है। पुलिस की लाठी भी उन्हें खानी पड़ती है, चोरबाजारियों के गुण्डे सताते है। भूखे दम किसान लाइन लगा कर खड़े रहते है लेकिन उन्हें डीजल नहीं मिलता है। इतनी बुरी हालत आज है जबकि रबी की फसल की सिंचाई का काम चल रहा है। आज उन्हें अपने पम्पिंग सेट चलाने के लिए भी डीजल नहीं मिल रहा है।

सरकार ने गावों में बहुत से डीजल पम्प सैंक्शन पम्प किये है मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हूं कि गावों में डीजल पम्प सैंक्शन किये गये है लेकिन उनका कार्यान्वियन रोक दिया गया है। जो डीजल पम्प इस समय गांवों में हैं उन्हे डीजल का कोटा कम दिया जाता है और शहरों में जो डीजल के पम्प हैं उनको ज्यादा कोटा दिया जाता है। माननीय मंत्री जी जब अपना उत्तर दें तो यह भी बताएं कि क्या गांवों में डीजल पम्प सैंक्शन किये गये है और उन्हें कब तक काम करने की इजाजत दे दी जाएगी ?

कब तक उनका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और इस दिशा में सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ? डीजल की चोर-बाजारी रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है, इस पर भी माननीय मंत्री जी प्रकाश डालें। अभी 90 हजार लीटर डीजल उत्तर प्रदेश के सुल्तानापूर जिले में पकड़ा गया, लेकिन जो चोर-बाजारिए थे उनको छोड़ दिया गया और जिन अफसरों ने 90 हजार लीटर डीजल पकड़ा था, उनका तबादला कर दिया गया। सत्ताधारी दल के लोगों की साजिश से चोर बाजारी हो रही है, इससे जनता को परेशानी हो रही है। यह बड़े शर्म की बात है सत्ताधारी दल के लोग इसमें इन्वाल्व हैं। इसलिए माननीय मंत्री जी निश्चित तौर पर जांच करवाएं और देखें कि क्या असलियत है।

मान्यवर मैं आगे यह कहना चाहूंगा कि गोरखपुर जिले के अंदर डीजल की कमी

[श्री हरिकेश बहादुर]

के विरोध में छात्रों किसानों ने आंदोलन किया तो सरकार ने पुलिस से कह कर उनको लाठियों से पिटवाया और तामम लोगों को जेलों में डाल दिया, बजाए इसके कि किसानों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाते, लोगों को पीटना और जेल में बंद करना ज्यादा आसान और सही समझा गया और यही काम ये कर रहे हैं। पूरे देश के अन्दर जगह-जगह लोगों को मारा जा रहा है, जान से मारा जा रहा है और सताया जा रहा है।

मान्यवर पूरे उत्तर प्रदेश में और खास-तौर से गोरखपुर वाराणसी मण्डलों में भयंकर कठिनाई डीजल की है और बिहार के अंदर काफी कठिनाई है। अभी कुछ दिन पहले हमने अखबारों में देखा था कि "ओपके" द्वारा प्राइसेस बढ़ा दी गई है, मेरे ख्याल में भारत को भी अपने इंपोर्ट बिल में 6 हजार करोड़ रुपया देना पड़ेगा, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट रुप से जानना चाहता हूं कि "ओपेक द्वारा तेल मूल्य में वृद्धि के कारण क्या आप भी डीजल के मूल्य में वृद्धि करने जा रहे हैं? दूसरी बात यह पूछना चाहता हूं कि "ओपेक" द्वारा, तेल मूल्य में की गई वृद्धि में क्या भारत को कोई छूट दी जाएगी? तीसरी बात मान्यवर मैं यह जानना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश गोरखपुर-वाराणसी बिहार और पूरे उत्तर प्रदेश में डीज़ल की कमी को दूर करने के लिए क्या सरकार एक्स्ट्रा कोटा देगी?

मान्यवर, एक विशेष न्यूज आयटम हमने न्यूज पेपर्स में देखा था कि 34 विदेशी कंम्पनियों को तेल की खोज के लिए यहां बुलाया जा रहा है, इसमें क्या सच्चाई है? ओ० जी० सी० आखिर क्या कर रहा है? बाहर से कंम्पनियों को बुलाना पड़ रहा है। ये कंम्पनियों जो कोटा कलेक्ट करेंगी क्या वह ओ० एन० जी० सी० को देंगी? क्या इनको पैसे के अतिरिक्त उत्पादन में भी हिस्सा देंगे? इन तमाम सवालों का जवाब आना चाहिए। सरकार ने चुप्पी साध ली है, कुछ नहीं किया जा रहा है। पूरे देश में तेल संकट है, उत्तर प्रदेश में और पूरे हिन्दुस्तान के अंदर विशेष रूप से किसानों में डीजल का गहरा संकट है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जितने प्रश्न मंत्री जी से पूछे हैं उनका वे स्पष्ट रूप से उत्तर दें और बताएं कि क्या उत्तर प्रदेश को एकस्ट्रा कोटा अलाट करेंगे?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी: उपाध्यक्ष महोदय, तेल के इस दुनियाभर के भीषण संकट के समय में भी भारतवर्ष में तेल का संकट नहीं है, मगर यह दुर्भाग्य की बात है कि चन्द राजनीतिक दलों ने और व्यक्तियों ने किसानों को भड़काने और जहां कमी नहीं है वहां कमी दिखलाने का एक रास्ता अपनाया है।

श्री हरिकेश बहादुर: उसमें आपकी पार्टी भी शामिल है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी: मैंने आंकड़ों से बताया है कि डीज़ल की पेट्रोल की और किसी चीज की कोई कमी नहीं है। न केवल अक्तूबर में जो दिया था उसे नवम्बर में बढ़ाया है लेकिन नवम्बर में जो दिया था उसे दिसम्बर में भी बढ़ाया है। मेरी

प्रार्थना है कि इस स्केरस कमोडिटी के बारे में कोई स्कारसिटी की फ़िजा पैदा नहीं की जानी चाहिए। अगर नहीं कमी है तो मदद करके उसको हल करवाने की कोशिश होनी चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि कम से कम तेल के एक खाते को तो आप छोड़ दें जिस में आन्दोलनों का रवैया न अपनाएं और हकीकत को देख कर काम करें। फारेन एक्सचेंज खर्च करके तेल मंगाया जा रहा है और किसानों को हम मदद दे रहे हैं। डीजल की कोई कमी नहीं है। कैरोसीन आयल के बारे में तो यह कहा जाता है कि इसको चोरी छिपे डीजल में मिलाया जाता है लेकिन डीजल की चोरी की बात कुछ नई लगती है। हो सकता है कि कहीं कोई एक आध ऐसी घटना हुई हो लेकिन यह राज्य सरकारों के देखने का काम है। राज्य सरकारों ने जब जब कोटा बढ़ाने की बात कही है मैंने कोटा बढ़ाया है और आगे भी अगर आवश्यकता होगी तो उसको बढ़ाया जा सकता है। मूल ब्यान में भी मैंने कहा है कि डीजल की कोई कमी किसानों के लिए नहीं होने दी जाएगी और अगर उसका और अधिक आयात करना पड़ा तो वह भी किया जाएगा। मेहरबानी करके वितरण के काम में मदद करने की आप कोशिश करें बजाय इसके कि जबर्दस्ती स्केरसिटी की आबोहवा फैलाएं।

ओपेक ने कीमतें बढ़ाई है, यह सवाल इस में से नहीं उठता है। यह प्रश्न कालिंग एटेंशन में नहीं आता है —

श्री हरिकेश बहादुर : बता तो सकते हैं।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : फाइनेंशियल मैटर्ज में पहले से कोई बताता है ? आप तो समझदार आदमी हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप गलतफहमी में क्यों हैं ? आप की समझदारी पर सन्देह हो गया है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : आप हमेशा करते रहते हैं। इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है।

जहां तक 34 तेल कम्पनियों को बुलाने का सवाल है वह सवाल भी इस में से नहीं उठता है। लेकिन उसके बारे में मैंने बार-बार कहा है और यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि देश में तेल की खोज को तीव्र करने के लिए विदेशी कम्पनियों को हमने आमंत्रित किया है। प्री-क्वालिफाई करके 67 में से 34–35 कम्पनियों को शार्ट लिस्ट किया है ; उन से बहस मुबाहिसा हो रहा है। हमारी टीम्ज पैरिस और वाशिंगटन गई हुई हैं। ऐसी सूरत में जब उन से सब शर्तें और शर्तनामा तय नहीं हो जाता है यह कहना मुश्किल है कि किन कंडिशंज पर काम शुरू होगा। लेकिन ओ एन जी सी और आयल इंडिया के लिए भी काफी काम है और उनके काम को आगे बढ़ाने का भी प्रोग्राम रखा है। दोनों के काम को आगे बढ़ाते हुए देश में तेल की खोज को तेज़ करने के उद्देश्य से इन कम्पनियों को आमंत्रित किया गया है।

SHRI NIREN GHOSH (Dum Dum): Sir, the policy of the Government on Oil has been a disastrous policy for our country. Would the hon. Minister tell us that there has been a scarty of diesel or scarcity of petrol products? A huge amount of foreign exchange has already been spent and more will be spent in the coming months for importing Oil and petroleum products. Why have you given up the idea of coal based industries? Many industries have been converted into diesel base industries in order to give Indian money on a platter to the

[Shri Niren Ghosh]

foreign multi-nationals. Now, would you reverse this policy so that the precious foreign exchange can be kept in reserve? I know for certain that many industrial concerns would get whatever quantity of diesel they want from the depots, for the petrol pumping stations at a premium of 25 per cent more price. So, this is sold in black-market. I want to know whether the hon. Minister is aware of this fact or not. That is low diesel is being distributed. Would you kindly make a surprise check of those depots and pumping stations where blackmarketing is being done? This practice is going on throughout the country. Now, there is a big rise in petrol price and over and above that a good percentage of excise duty is also added. The Government should cut the excise duty so that the price of diesel is within the reasonable limit and the common man and the agricultrists are able to purchase these products. They are now forced to pay such high prices. The Government must make serious efforts to do away with the blackmarketing in diesel. I would like to know whether for this purpose you would introduce rationing system for diesel throughout the country with proper book-keeping and proper check-up. So, that diesel or petrol cannot be sold in the black market as it is being done now. This would also ensure adequate supply to the consumers.

Further, is it also a fact that you have allotted different quantities of diesel to different States in a discrminatory manner? Whereas some States have got one lakh tonnes of diesel per month, some States get as less as 34,000 tonnes. For example, though the demand for diesel in West Bengal is 85,000 tonnes per month minimum, and they were getting 65,000 tonnes, now, you are giving them only 55,000 tonnes per month. I have myself seen with my own eyes very long queues at the diesel retail outlets of trucks and lorries. Sometimes these lorries do not ply for two or three days for want of diesel. These queues are very very long . It this is what has happened in West Bengal, obviously, it would be the case in other parts of the country also. You have made a mess of the whole distribution system of diesel and petrol.

I do not know why you have engaged 34 foreign countries for oil exploration in the country. The country has been divided in them. A very little work has been left for the ONGC.

Will you give an assurance that though there is a hike in the OPEC prices of oil. the price of diesel will not be raised further so that it remains within the limit of purchase by common people? Whereas the States are complaining of diesel shortage, on the contrary you are saying that you have supplied them the sufficient quatities. It is an untrue statement.

As I said, in order to ensure proper and adequate distribution of diesel would you introduce rationing of diesel and would you give up dieselization on a vast scale? Will you keep on to coal, whrever you can?

SHRI P. C. SETHI: I may draw the atention of the hon. Member to the fact that whereas West Bengal got the allocation of 43,746 tonnes of diesel in the month of November, 1979, we gave them 45,900 of diesel in November 1980. Therefore, to say that 5 per cent growth rate formula has not been applied to West Bengal is not correct.

I would also like to inform his that when the Chief Minister of West Bengal saw me in this connection and I made the allocation from 45,000 to 50,000 tonnes, he was more than satisfied. Then came a further request and I raised it from 50,000 to 54,000 and now the Chief Minister is absolutly satisfied and if there is a communication gap between you and him, I cannot help.

SHRI NIREN BHOSH: The State Transport Minister told me a few days ago that they were getting a supply of 65,000 tonnes; that has

been reduced to 55,000 tonnes and it is very difficult to manage with that.

SHRI P. C. SETHI: The Chief Minister was more than satisfied with the allocation which I have made to him and with the surplus quota which I have given. But, if there is any difficulty, if the Bengal Government comes forward with any further request of any *ad hoc* allotment, we shall definitely consider it.

Sir, as far as the question of rationing is concerned, I have said it more than once that we are not in favour of any rationing. It creates more problems. It creates a scare. The panic buying starts and the black-market also starts. Therefore, as far as possible, as far as we can try to tide over the difficulty, we would not introduce rationing in this item.

Sir, as far as the distribution to the various areas is concerned, I fully agree with the Hon. Member that the dieselisation of the various units and even of the Railways, should be considered from the point of view of the national requirement. The only answer to change of dieselisation is not going back to coal because that would lessen the speed of the trains. The only answer to the removal of dieselisation is the electrification of the track and that can alone help.

But, as far as the industries are concerned, I would like to remind the Hon. Member that we are trying to cut the fuel oil which is required by the industry and requesting them to use coal wherever they can but, on account of transport bottlenecks, many of the industries are not in a position to get coal in time and, therefore, for example, the Dhuvaran Power stations at Gujarat, has not been able to switch over only because coal cannot reach them. However, the situation is improving and we are trying our best to replace fuel oil, wherever we can.

Sir, as far as these companies are concerned, I would again like to request Mr. Ghosh that he has to see the whole problem from a very broad perspective because the consumption of petroleum and crude today is in the vicinity of about 33 to 34 million tonnes but, at the speed at which we are increasing our demand and the growth-rate is coming up, by the year 2000, we would be in the vicinity of about 93 million tonnes and, therefore, our problem is that we will be completely exhausted and drained if we do not produce oil resources and it is not only the question of producing oil resources, but producing it in time, so that we can meet the requirement of the country. It does not necessarily mean that we should not try to conserve and check the growth-rate which is increasing at a fast pace, but the same time research for oil is absolutely essential. There may be difference of opinion. There may be difference of outlook. But, the Government has taken a decision that these companies must be invited and we should increase the search for oil in a big way.

Sir, as far as the price-hike is concerned, the question of any assurance or any declaration whether price rise is coming, or any assurance that price rise would never come, is not possible, because it does not revise because of the calling attention notice.

प्रो० सत्य देव सिंह (छपरा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि ईरान ईराक युद्ध के बीच हमारे मंत्री महोदय ने और भारत सरकार ने पेट्रोलियम की आपूर्ति का काफी सुन्दर ढंग से इन्तज़ाम किया है, और इसीलिए वे धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि 20–सूत्री कार्यक्रम समन्वय समिति की बैठक जो छपरा में हुई, उसमें ऐसा कहा गया था कि बिहार प्रदेश के कोटे में कटौती की गई है और सारण जिले में कटौती इसी कारण हुई है। इसी के चलते हमारे क्षेत्र में डीज़ल की बहुत कमी है और किसानों में काफ़ी परेशानी है। सरकार ने संभवत: काफी मात्रा में डीज़ल की आपूर्ति

[प्रो० सत्य देव सिंह]

की है, किन्तु किसानों को डीज़ल पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता, इसका कारण यह है कि वहां के जिला पदाधिकारी जो कि बड़े-बड़े ऊंचे-ऊंचे पदों पर विराजमान हैं, सब चोरबाजारी में लिप्त हैं। इसके कारण वहां पर संकट बहुत बढ़ा हुआ है। किसानों को एक डीज़ल पम्प के लिए सप्ताह में पांच या दस लिटर डीज़ल मिलता है, जिससे काम नहीं चलता है। मैंने परामर्शदात्री समिति में भी मंत्री महोदय से आग्रह किया था कि उनका काम डीज़ल की आपूर्ति करना तो है ही, साथ ही साथ वह ऐसी व्यवस्था भी करें कि अगर प्रदेश सरकार के पदाधिकारी कोई गोल-माल करते हैं, तो वह उन पर नियंत्रण रख सकें। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण काम है, जिसकी ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। अगर उनके पास इस समय कोई प्रावधान नहीं है, तो वह ऐसी व्यवस्था करें कि किसानों को जो डीज़ल दिया जा रहा है, उससे उनको लाभ हो सके।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य का भी कोटा बढ़ाने का प्रयत्न किया गया है। अक्तूबर में बिहार को 30,280 मीट्रिक टन डीज़ल प्राप्त हुआ था। नवम्बर में 37,000 मीट्रिक टन दिया गया और दिसम्बर में उसको बढ़ा कर 41,000 मीट्रिक टन कर दिय गया। हम यह मानिटर कर रहे हैं कि एलोकेशन के मुताबिक सामान वहां पर पहुंच जाये। मेरी सूचना के हिसाब से सामान एलोकेशन के मुताबिक पहुंच रहा है। जहां तक राज्य में वितरण का प्रश्न है, कौन से जिले में कितना भेजा जाये, यह स्थानीय सरकार तय करती है। अगर किसी जिले या तहसील में कोई कठिनाई हो, तो माननीय सदस्य केन्द्रीय सरकार का ध्यान भी उसकी तरफ़ आकर्षित कर सकते हैं। अगर उनकी तरफ़ से कोई विशेष सूचना आयेगी, तो हम राज्य सरकार के साथ उसका निर्णय करने की कोशिश करेंगे माननीय सदस्य ने राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा कुछ गड़बड़ किये जाने की शिकायत की है। यह मसला तो उन्हें राज्य सरकार के साथ ही उठाना होगा।

12.37 hrs.

ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY (SECOND AMENDMENT) BILL

THE MINISTER OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE (SHRI S. B. CHAVAN): Sir, I beg to move for leave to withdraw a Bill further to amend the Aligarh Muslim University Act, 1920.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

> "That leave be granted to withdraw a Bill further to amend the Aligarh Muslim University Act, 1920."

DR. SUBRAMANIAM SWAMY (Bombay North-East): Sir, I beg to leave of the House to oppose the withdrawal of the Bill. I will explain. The Aligarh Muslim University is a very important institution. It is an institution of national importance, and we would like to see it flourish. When the Janata Government was in power, we brought in a Bill which was, in effect, to satisfy the aspirations of the students of that University and, in particular, the community of Muslims who regard this as a very important centre for them. Earlier on, when the previous Indira Gandhi Government was there, some amendments were brought in, which made them very unhappy. And, therefore, in order to remove that unhappiness, we brought in a Bill. Then the House was dissolved, and the whole thing lapsed.

Now, this Government has already brought two Bills. It brought in one Bill, withdraw it and brought in another. Now, they are withdrawing it.